

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अंकित अग्रवाल

बनाम

बिहार एवं झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं अन्य।

2024 का सिविल रिट वाद संख्या 5202

18 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री

अशोक कुमार पाण्डेय)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148A के अंतर्गत प्रारंभ की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही क्षेत्राधिकार की कमी और समयसीमा के उल्लंघन के कारण अमान्य थी?
- क्या पुनर्मूल्यांकन आदेश को झूठे आधार और सामग्री के प्रकटीकरण की अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता को अधिनियम, 1961 की धारा 148A(बी) के तहत कोई प्रभावी कारण बताओ नोटिस प्रदान नहीं किया गया। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.03.2022 के कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया, स्वयं नोटिस को वैध और विधि की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बना सकता। वित्त अधिनियम, 2021 के लागू होने के पश्चात, प्रतिवादीगण केवल तभी

अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर सकते थे जब धारा 149(1)(बी) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होतीं। (अनुच्छेद 41)

याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की शुरुआत धारा 148A(बी) के अंतर्गत जारी नोटिस में दी गई गलत जानकारी के आधार पर की गई थी, जो किसी भी सामग्री से समर्थित नहीं थी। अतः दिनांक 06.04.2022 को धारा 148 के तहत नोटिस जारी कर कार्यवाही आरंभ करना विधि के अनुसार दोषपूर्ण माना जाएगा। (अनुच्छेद 42)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (अनुच्छेद 44)

न्याय दृष्टान्त

राजीव बंसल बनाम भारत संघ, [2024] 469 ITR 46 (SC); सालिक खान बनाम असेसमेंट यूनिट, CWJC संख्या 7568/2024; भारत संघ बनाम आशीष अग्रवाल, (2023) 1 SCC 617; गणेश दास खन्ना बनाम आईटीओ, [2024] 460 ITR 546 (Del); इन्वेंटर्स इंडस्ट्रियल कॉर्प. लि. बनाम सीआईटी, (1992) 194 ITR 548; चतुर्भुज गतानी बनाम आईटीओ, (2024) 468 ITR 295; चंद्रशेखर बनाम प्र. सीआईटी, CWJC संख्या 8351/2024; जी.के.एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लि. बनाम आईटीओ, (2003) 1 SCC 72

अधिनियमों की सूची

आयकर अधिनियम, 1961: धारा 142(1), 144, 147, 148, 148A (b), 148A (d), 149, 151, 156

मुख्य शब्दों की सूची

आयकर रिटर्न; पुनर्मूल्यांकन; धारा 148A; क्षेत्राधिकार त्रुटि; कारण बताओ नोटिस; छूटा हुआ मूल्यांकन; धारा 149 के अंतर्गत समयसीमा; कर मांग; छूट प्राप्त दीर्घकालिक पूंजी लाभ; प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश एवं कर मांग पत्र से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता; श्री अक्षत अग्रवाल, अधिवक्ता; श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता; श्री विकास खन्ना, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्रीमती अर्चना सिन्हा @ अर्चना शाही, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का सिविल रिट वाद संख्या 5202

=====

अंकित अग्रवाल, पिता- श्री गणेश अग्रवाल, वर्तमान निवासी- फ्लैट संख्या 413, एथेना अपार्टमेंट, जय सिंह राजमार्ग, पी. एस. बानी पार्क, जिला जयपुर, (राजस्थान) ।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखंड, पहली मंजिल, सी. आर. भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

2. मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखंड, पहली मंजिल, सी. आर. भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना।
3. आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर, अतिथि भवन, साहू रोड, मुजफ्फरपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-II, मुजफ्फरपुर चंद्रलोक भवन, चंद्रलोक चौक, नया तोला, मुजफ्फरपुर।
5. आयकर अधिकारी, वार्ड 2 (5) सीतामढ़ी, चंद्रकला भवन, भावदेवपुर, सीतामढ़ी।
6. मूल्यांकन प्राधिकरण, राष्ट्रीय गुमनाम/चेहराविहीन मूल्यांकन केंद्र, आयकर विभाग, नई दिल्ली।

..... प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता श्री अक्षत अग्रवाल, अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता श्री विकास खन्ना, अधिवक्ता
प्रतिवादीओं के लिये	:	श्रीमती अर्चना सिन्हा @ अर्चना शाही, सीनियर एससी

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तिथि: 18-04-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और आयकर विभाग (प्रतिवादियों) के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. यह रिट आवेदन निम्नलिखित राहतों हेतु दायर किया गया है:

“(i) डी. आई. एन.:आई. टी. बी. ए./ए. एस. टी./एफ./144 (एफ. सी. एम.)/2023-24/1061726288 वाले दिनांक 29.02.2024 के कारण दिखाएँ नोटिस को रद्द करने हेतु (1) जो प्रतिवादी विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र के के बिना जारी किया गया क्योंकि विवादित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही की शुरुआत ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (बी) के अधीन गलत आधार पर जारी नोटिस को स्वीकार करके शुरू की गई थी।

(ii) डी. आई. एन. और आई. टी. बी. ए./ए. एफ. टी./एफ./148 ए/2022-24, सूचना संख्या 1042559776 वाले दिनांक 06.04.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (डी) के अधीन जारी क्योंकि यह झूठे आधार पर पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता विवरणी दाखिल नहीं करता है और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आय के मूल्यांकन से बच गया है, जबकि आक्षेपित कारण बताओ नोटिस में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए अपना आयकर विवरणी दाखिल किया था।

(ग) निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम, 1971 की धारा 142 के तहत की गई संपूर्ण पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही और जांच को अलग रखने के लिए क्योंकि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए(डी) के अधीन दिनांक 06.04.2022 को जारी विवादित आदेश के आधार पर शुरू की गई थी, जो अपने आप में अवैध, मनमाना और विधि की दृष्टि से गलत है।

(iv) इस घोषणा के लिए कि यदि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (डी) के अधीन दिनांक 06.04.2022 को जारी न्यायालय का विवादित आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के संदर्भ में समयबद्ध होने के लिए पारित नहीं किया गया होता, यदि प्रतिवादी विभाग ने 25,90,000- रुपये की राशि के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के शीर्ष के तहत छूट प्राप्त आय के गलत दावे का आरोप लगाते हुए

नोटिस जारी किया होता। क्योंकि नोटिस जारी करने की सीमा 3 साल की है;

(v) इस घोषणा के लिए कि प्रतिवादी विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 ए (बी) के तहत एक नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता पर रुपये 1,04,90,899/- की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के तहत नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित सीमा की लंबी अवधि का लाभ उठाने के एकमात्र इरादे के साथ, कर विवरणी दाखिल न करने और निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर से बचने का आरोप लगाने और आय पर कर का भुगतान न करने जैसे कि धारा 148 ए (बी) के तहत नोटिस जारी करके किया गया होता का आरोप लगाया गया है, यदि मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा धारा 148 ए (बी) के अधीन रुपये 25,90,000-के दीर्घकालिक पुंजीगत लाभ के लिये दायर कथित दावे के आयकर विवरणी की जांच करने के बाद, इसे निराशाजनक रूप से रोक दिया गया होगा क्योंकि, 50,00,000/- रुपये से नीचे की राशि के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 149 के अधीन नोटिस जारी करने की सीमा 3 साल है; और/या माननीय न्यायाधीश द्वारा, किसी अन्य आदेश/आदेश के लिए जो इन तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकता है।”

मामले के संक्षिप्त तथ्य

3. याचिकाकर्ता भारत का एक नागरिक है जिसने प्रतिवादी, आयकर अधिकारी, वार्ड 2 (4), सीतामढ़ी, के समक्ष अपना आयकर विवरणी मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के लिये पी.ए.न. ए.आइ.टी.पी.5484 ए में दाखिल किया है। वे मेसर्स सुभलक्ष्मी दल मिल, हजारीमल रोड, बैरगनिया, सीतामढ़ी और मेसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, राजधानी कृषि उपज मंडी, सिक्का रोड, कुकरखेड़ा, जयपुर, कुकरखेड़ा में स्थित है, के नाम और शैली में एक स्वामित्व वाली कंपनी चला रहे हैं।

4. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसने अपना आयकर विवरणी, निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्तीय वर्ष 2014 -15) 30.03.2016 को, जिसमें इसके विवरणी की गणना के आधार पर, याचिकाकर्ता ने की कुल आय रु. 7,99,950-जिस पर उन्होंने रु. 96, 345/- कर जमा करने का खुलासा किया था। उन्होंने 25,04,808-शेयरों की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में 'अन्य शीर्ष' के तहत एक लाख रुपये तक के कर से छूट का दावा किया था। ।

5. याचिकाकर्ता की स्वामित्व फर्म के लाभ और हानि खाते, तुलनपत्र और लेखा पुस्तकों का लेखा-परीक्षण एक अनुबंधित लेखाकार द्वारा किया गया था, जिसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 एबी के तहत लेखा-परीक्षण रिपोर्ट जारी की थी (जिसे इसके बाद '1961 का अधिनियम' कहा गया है)। आयकर विवरणी स्वीकृति और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति रिट आवेदन के साथ क्रमशः अनुलग्नक 'पी/1' और 'पी/2' के रूप में संलग्न है।

6. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि छह साल पूरे होने के बाद, याचिकाकर्ता को आकलन वर्ष 2015-16 के संबंध में 06.04.2022 पर 1961 के अधिनियम की धारा 148 ए(डी) के अधीन कथित रूप से विवादित आदेश पारित किया गया था। दिनांक 06.04.2022 के आदेश की एक प्रति रिट आवेदन के लिए अनुलग्नक 'पी/3' है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को विवरणी दाखिल न करने के कारण दिनांक 23.03.2022 1961 के अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के अधीन नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस में कहा गया है कि मॉड्यूल "नॉन-फाइलिंग ऑफ रिटर्न" के तहत इनसाइट पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता को एक नोटिस दिया गया था जिसमें गलत आरोप लगाया गया था कि उसने मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नोटिस (अनुलग्नक 'पी/3') के अनुसार आक्षेपित आदेश में यह आरोप लगाया गया है कि संबंधित मूल्यांकन वर्ष में, याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक में कुल 60,92,995/- रुपये नकद में जमा किए थे और आगे 43,97,919-रुपये का लेनदेन किया था। इन सूचनाओं के आधार पर, मूल्यांकन अधिकारी का विचार था कि याचिकाकर्ता के विभिन्न स्रोतों से उसकी कुल आय रु 1,04,90,899/- थी, परंतु, विवरणी दाखिल न करने के कारण लेकिन वह कर की पेशकश करने में विफल रहा था, इस प्रकार, यह मूल्यांकन से बचने का मामला है। इन तथ्यों पर, 1961 के अधिनियम की धारा 148ए (डी) के अधीन दिनांक 06.04.2022 को जारी विवादित आदेश और 1961 के अधिनियम की धारा 148 के अधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्धारण अधिकारी (अनुलग्नक 'पी' 4 ') से दिनांक 30.01.2023 को पत्र प्राप्त होने पर, उन्होंने तुरंत एक जवाब दायर किया और इसे निर्धारण अधिकारी के ध्यान में लाया कि याचिकाकर्ता आयकर का एक नियमित निर्धारिती है, उनकी लेखा पुस्तकों का वार्षिक रूप से अंकेक्षण किया जाता है और प्रतिवादी-विभाग से अनुरोध किया कि वह याचिकाकर्ता के विवरणी के मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन के लिए शुरू की गई विवादित कार्यवाही को हटा दे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विशिष्ट उत्तर के बावजूद, प्रतिवादी-विभाग ने 1961 के अधिनियम की धारा 142(1) के तहत मूल्यांकन के लिए दिनांक 07.06.2023 को नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के संबंध में कुछ विस्तृत दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिस का अनुपालन किया और दिनांक 19.06.2023 और 07.07.2023 के पत्र के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने धारा 142 (1) के तहत जारी किए गए दो नोटिसों का अनुपालन प्रस्तुत किया, फिर भी प्रतिवादी-विभाग ने धारा 142 (1) दिनांक 30.10.2023 के तहत तीसरा नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने नोटिस का अनुपालन किया

और सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जो उसके पास सबसे अच्छी तरह से उपलब्ध थे।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर तथ्यों से यह स्पष्ट है कि गलत आधार पर और गलत जानकारी के आधार पर, 1961 के अधिनियम की धारा 149 के तहत निर्धारित सीमा की लंबी अवधि का लाभ उठाने हेतु, 1961 के अधिनियम की धारा 148 ए (डी) के अधीन दिनांक 06.04.2022 को आदेश पारित किया गया था।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 29.02.2024 को निर्धारण इकाई, आय कर विभाग के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 29.02.2024 का विवादित कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया है, जिसके द्वारा दीर्घकालिक लाभ रु 25,90,000- के शेयरों की बिक्री के कारण फर्जी होने का आरोप लगाया गया है और याचिकाकर्ता को यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता पर उक्त परिवर्तन क्यों नहीं लगाया जाए। विभाग ने याचिकाकर्ता द्वारा तरंग परियोजना के 7000 शेयरों की बिक्री की आय पर संदेह किया है, जिसे याचिकाकर्ता ने मेसर्स तुषार (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से दिनांक 13.06.2009 अनुबंध संख्या 13 के माध्यम से खरीदा था, जिसे बाद में याचिकाकर्ता ने हिंदुस्तान ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेच दिया था। उक्त शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय याचिकाकर्ता के बैंक खाते में प्राप्त की गई थी और इसकी लेखा पुस्तकों में भी विधिवत लेखा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा छूट के रूप में दावा किए गए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को प्रतिवादी-विभाग द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है।

13. रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी-निर्धारण प्राधिकरण, आयकर मूल्यांकन इकाई, ने 1961 के अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144, 144 (बी) के तहत 18.03.2024 को मूल्यांकन आदेश पारित किया और 18.03.2024 को अधिनियम की धारा 156 के तहत मांग की सूचना दी। याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन आदेश और मांग के नोटिस दोनों को दिनांक 18.03.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विभाग ने याचिकाकर्ता को

रु 19,45,394/- की राशि जमा करने का आदेश दिया गया। मूल्यांकन आदेश और मांग की सूचना को अनुलग्नक 'पी/11' के रूप में जोड़ते हुए अंतर्वर्ती आवेदन संख्या-1/2024 दायर किया गया है और उक्त अंतर्वर्ती आवेदन द्वारा रिट आवेदन में संशोधन किया गया है। इस न्यायालय ने दिनांक 10.02.2025. के आदेश के माध्यम से संशोधन आवेदन की अनुमति दी और विभाग को वाद के सभी पहलुओं का जवाब देते हुए एक समेकित जवाबी शपथपत्र दायर करने का अवसर दिया गया।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ बनाम राजीव बंसल [2024] 469 आई. टी. आर. 46 (एस. सी.)** में रिपोर्ट किया गया, के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह तथ्य प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुरानी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल, 2021 और 30 जून, 2021 के बीच जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिसों पर इस आधार पर ध्यान दिया है कि (i) 1 अप्रैल, 2021 से वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा धारा 147 से 151 को प्रतिस्थापित किया गया था; (ii) किसी भी बचत खंड के अभाव में, राजस्व, 1 अप्रैल, 2021 के बाद केवल नई व्यवस्था के प्रावधानों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू कर सकता है क्योंकि वे उपचारात्मक, लाभकारी और निर्धारिती के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए थे और (iii) केंद्र सरकार पहले से मौजूद इसके प्रत्यायोजित अधिकार कानून को फिर से सक्रिय करने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नए प्रावधानों को पिछले निर्धारण वर्षों से संबंधित कार्यवाही के लाभ के संबंध में भी उपलब्ध कराया जाएगा। बशर्ते कि धारा 148 का नोटिस 01.04.2021 को या उसके बाद जारी किया गया हो।

15. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस वाद में निर्धारण अधिकारी "केवल जानकारी" के आधार पर, आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के कब्जे का कोई सबूत नहीं था, जिससे पता चलता कि रु 50 लाख या उससे अधिक की बची हुई राशि के कर के मूल्यांकन का आकलन नहीं हो पाया है। विद्वान अधिवक्ता

ने 11 मई, 2022 के सीबीडीटी निर्देश संख्या 1 के पैराग्राफ '7.8' और '8.1' पर भरोसा किया है।

16. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 50 लाख रुपये की सीमा से बचने के लिए बिना किसी ठोस साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन शुरू करने के लिए विवादित आदेश में बढ़ी हुई राशि दिखाई गई है। जो पुनर्मूल्यांकन शुरू करने के लिए एक पूर्व शर्त है और जांच के बाद आय से बचने वाले मूल्यांकन का अंतिम आंकड़ा केवल रु 29 लाख जो निश्चित रूप से मूल्यांकन वर्ष के अंत के छह साल बाद नोटिस को ट्रिगर नहीं कर सकता था। इस सूचना का आधार कि निर्धारित रिटर्न दाखिल नहीं करता है, त्रुटिपूर्ण है।

17. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अधिकार क्षेत्र की कमी मामले की जड़ तक जाती है और इस मामले में मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की गई है जो पूरी पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को दूषित कर देगी। विद्वान अधिवक्ता ने **आविष्कारक औद्योगिक निगम लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. ने 1991 में एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 655 में बताया: (1992) 194 आईटीआर 548: (1991) 96 सीटीआर 206** के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय पर पर भरोसा किया है।

18. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आयकर कानूनों में संशोधन पेश करते समय वित्त मंत्री का भाषण **गणेश दास खन्ना बनाम आयकर अधिकारी और अन्य के मामले में । [2024] 460 आई. टी. आर. 546 (दिल्ली)** में रिपोर्ट किया गया, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में पाया जा सकता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल गंभीर कर चोरी के मामलों में जहां 50 लाख रुपये से अधिक की आय को छिपाने का सबूत है, क्या पुनर्मूल्यांकन तीन साल की निर्धारित सीमा अवधि से आगे खोला जा सकता है। इसके लिए विभाग के उच्चतम स्तर से मंजूरी लेनी होती है।

19. विद्वान अधिवक्ता ने आगे सालिक खान बनाम आकलन इकाई, आयकर विभाग और अन्य. (सी. डब्ल्यू. जे. सी नं. 7568/ 2024) के वाद में इस न्यायालय की विद्वान खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 148 ए के अधीन नोटिस जारी करते समय, राजस्व को 30 दिनों के भीतर उस जानकारी और तत्वों की आपूर्ति करनी होगी जिस पर भरोसा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान वाद में धारा 148 ए (बी) के अधीन नोटिस जारी करते समय, मूल्यांकन प्राधिकरण ने धारा 148 ए के तहत नोटिस के अनुलग्नक में दी गई जानकारी के समर्थन में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई। विद्वान अधिवक्ता ने राजीव बंसल (सु.को.) के वाद में निर्णय के पैराग्राफ '101' पर भरोसा करते हुए कहा है कि यह विशेष रूप से निर्धारिती को प्रासंगिक सामग्री की आपूर्ति की बात करता है जो मानित नोटिस का आधार है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को पावती (अनुलग्नक 'पी/1') और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के माध्यम से यह प्रस्तुत करने के लिए लिया है कि याचिकाकर्ता ने समय पर अपना विवरणी दाखिल किया था और 25,04,808- लाख रुपये की छूट प्राप्त आय का दावा किया था। यह भी बताया गया है कि धारा 148 ए के तहत नोटिस में, आकलन प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि उसके बैंक खाते में कार्यवाही के दौरान 20 लाख रु. के किसी भी नकद जमा की कोई चर्चा नहीं होती है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह दर्शाता है कि धारा 148 ए के अधीन नोटिस जारी करते समय, मूल्यांकन प्राधिकरण ने राशि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था।

प्रतिवादीओं का रुख

20. विभाग के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने रिट आवेदन का विरोध किया है। विभाग की ओर से एक जवाबी शपथपत्र दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती को 1961 के अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत एक नोटिस दिया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि अधिनियम की धारा 148 के तहत उसे नोटिस क्यों जारी नहीं किया जाए। निर्धारिती ने दिनांक 23.03.2022 के कारण बताए जाने के नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए यह माना गया कि निर्धारिती की कुल आय रु 1,04,90,914/- विभिन्न स्रोतों से जो मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के लिए मूल्यांकन से बच गए थे और तदनुसार धारा 148(ए)डी

के अधीन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद 06.04.2022 को आदेश पारित किया गया था।

21. जवाबी शपथपत्र में निर्धारिती को दिए गए अवसर का विवरण शामिल किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि धारा 148 ए (बी) के अधीन 23.03.2022 को एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद, निर्धारिती ने अपनी आय विवरणी दाखिल नहीं की। बाद में, वाद को मूल्यांकन कार्यवाही के लिए फेसलेस युनिट को स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्वीकार किया जाता है कि मूल्यांकन के दौरान, फेसलेस असेसिंग ऑफिसर (एफ. ए. ओ.) ने पाया कि निर्धारिती ने 30.03.2016 को अपनी कुल आय रु. 7,99,960- की आयकर विवरणी दाखिल की थी, जिसमें एफ. ए. ओ. ने पाया कि निर्धारिती ने मैसर्स तुषार (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से तरंग परियोजना के 7000 इक्विटी शेयर 13.06.2009 पर खरीदे थे, जिसे आगे किसी अन्य दलाल के माध्यम से 24.03.2015 पर बेचा गया था। जब निर्धारिती से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने दलाल का विवरण प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की। निर्धारिती द्वारा दिया गया कारण यह है कि चूंकि डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए बहुत पुराना था और उक्त दलाल के पास कोई डीमैट या व्यापार खाता भी नहीं था। उनके पास अपने नाम के शेयरों के हस्तांतरण के लिए कोई शेयर हस्तांतरण पर्ची नहीं थी। तरंग परियोजना स्क्रिप की खरीद की तारीख से यानी 13.06.2009 और 23.03.2015 तक उन्हें कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ था। दलाल कंपनियों को शेयरों की खरीद और हस्तांतरण के बारे में जानकारी के लिए अधिनियम की धारा 133 (6) के अधीन नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे दोनों आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे। इन परिस्थितियों में, इसे 1961 के अधिनियम की धारा 115 बी. बी. ई. के साथ पठित धारा 68 के अधीन एक अस्पष्टीकृत नकद ऋण के रूप में माना जाता है। निर्धारिती ने 04.03.2024 को जवाब दिया और कहा कि विचाराधीन दस्तावेज काफी पुराने हैं और उन्होंने चार सप्ताह के समय की मांग की। यह कहा गया है कि चूंकि वाद 31.03.2024 को परिसीमा द्वारा वर्जित होने वाला था, इसलिए एफ. ए. ओ. द्वारा 05.03.2024 को निर्धारिती को एक स्थगन

पत्र जारी किया गया था जिसमें निर्धारिती से 08.03.2024 तक कारण बताए जाने के नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। 08.03.2024 को, निर्धारिती ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें पहली बार, उसने गलत और गलत जानकारी के आधार पर धारा 148 ए और धारा 148 ए (डी) के तहत आदेश के तहत कार्यवाही को चुनौती दी।

22. इन परिस्थितियों में मूल्यांकन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है।

प्रतिवादीओ की ओर से प्रस्तुतियाँ

23. विभाग के लिए विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने अभिलेख प्रस्तुत किए हैं और धारा 148 ए के तहत नोटिस को देखते हुए जब ,इस न्यायालय द्वारा के धारा 148 ए के खंड (बी) तहत नोटिस के अनुलग्नक की सामग्री के संबंध में एक प्रश्न किया गया था, विभाग के लिए विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उक्त सूचना के अनुलग्नक का पहला पैराग्राफ गलत प्रतीत होता है और जो शायद सूचना के अनुलग्नक को तैयार करते समय कट एंड पेस्ट अभ्यास का परिणाम है। विद्वान वरीय स्थायी अधिवक्ता, हालांकि, प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक अनुलग्नक की मुख्य सामग्री का संबंध है, यह सही है और विभाग के अंतर्दृष्टि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है जो भारतीय स्टेट बैंक में कुल 20 लाख रुपये जमा, तथा 26,31,400-और रु 43,97,919/- का लेनदेन और आगे यह दिखा रहा था कि निर्धारिती ने रुपये के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में थे। 5,56,584- रुपये के इक्विटी शेयर बेचे थे।

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि धारा 148 ए (बी) के अधीन नोटिस पी. सी. सी. आई. टी., बिहार और झारखंड के पूर्व अनुमोदन के साथ जारी किया गया है। इस संबंध में, इस न्यायालय का ध्यान नोटिस के पैराग्राफ '4' की ओर आकर्षित किया गया है (प्रत्युत्तर के लिए अनुलग्नक 'ए')।

25. विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने से पहले, विभाग ने कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर

देने के बाद ही पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू की गई थी। अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पुराने कानून के तहत, विभाग के पास अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए छह साल उपलब्ध थे। छह साल की अवधि 31.03.2022 को समाप्त हो गई होगी, लेकिन अगर जवाब देने के लिए दिए गए समय को परिसीमा की अवधि की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है, तो धारा 148 के अधीन, नोटिस दिनांक 06.04.2022 को समय के भीतर मिल जाएगा।

26. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान वाद में, अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, याचिकाकर्ता अपना विवरणी दाखिल करने में विफल रहा। विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने जी. के. एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य एस. सी. सी. (2003) 1 72 में रिपोर्ट किया गया के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

27. विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 148 ए के अधीन नोटिस जारी करने के चरण में, केवल वह जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया है। चतुर्भुज गट्टानी बनाम आयकर अधिकारी और अन्य (2024) 468 आई. टी. आर. 295 में सूचित.:2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 3142:(2024) 336 सीटीआर 369 (राज), में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उचित अवसर की अवधारणा धारा 148 ए के अधीन विचार की गई जांच में निहित प्रतीत होती है। हालाँकि, यह देखना होगा कि क्या इस अवधारणा को निर्धारण अधिकारी की राय के समर्थन में सामग्री/साक्ष्य की आपूर्ति निर्धारण तक बढ़ाया जा सकता है कि कुछ आय मुल्यांकन से बच गई है। यह उनका निवेदन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने चतुर्भुज गट्टानी (सुपरा) के मामले में निर्णय दिया है कि धारा 148 ए को पढ़ने पर यह पाया जा सकता है कि वह धारा 148 ए (बी) के अधीन कारण बताओ नोटिस के समर्थन में किसी भी सामग्री/साक्ष्य की आपूर्ति के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करता है। विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने आगे इसे प्रस्तुत करने के लिए चंद्रशेखर बनाम प्रधान आयकर आयुक्त और अन्य. (सी. डब्ल्यू.

जे. सी. सं. 8351/2024) के वाद में इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ के निर्णयपर भरोसा किया है। उक्त मामले में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2020-2021 के संबंध में 28.03.2024 को धारा 148 ए खंड (बी) के अधीन नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि परिसीमा के उद्देश्य से दिनों की संख्या को नोटिस की तारीख 22.04.2024 से गिना जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने पाया कि दिनांक 22.04.2024 का नोटिस याचिकाकर्ता के दिनांक 28.03.2024 यानी दिनांक 31.03.2024 के जवाब अनुसार जारी किया गया था। माननीय खंड पीठ ने पाया कि धारा 149 का 5 वां और 6 वां परंतुक यह स्पष्ट करता है कि नोटिस के संदर्भ में देरी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि उक्त मामले में नोटिस का अर्थ है 28.03.2024 पर जारी किया गया पहला नोटिस और यह निर्धारित समय-सीमा के भीतर पाए जाने पर था यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारण अधिकारी का अधिकार क्षेत्र था।

28. विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश विधि के अनुसार हैं, इसलिए इसमें न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विचार करें

29. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। इस मामले में, पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होगा, वह पूरी तरह से 1961 के अधिनियम की धारा 149 के संदर्भ में है, जैसा कि वित्त अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया है, धारा 148 या धारा 148 ए के अधीन एक नोटिस जारी किया जा सकता था।

30. वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित धारा 149 में निम्नानुसार लिखा है-

नोटिस के लिए समय सीमा।

149. 56 [(1) संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, -

55. प्रासंगिक मामले कानूनों के लिए, टैक्समैन मास्टर गाइड टू इनकम-टैक्स एक्ट देखें।

56. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-1989

57. "जारी" शब्द के अर्थ के लिए, टैक्समैन की प्रत्यक्ष कर नियमावली, वोल्यूम.3 देखें।

⁵⁸ [(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि मामला खंड (ख)⁵⁹ [या खंड (ग)] के अंतर्गत नहीं आता है;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, लेकिन छह वर्ष से अधिक नहीं, तब तक बीत चुके हैं जब तक कि कर के लिए प्रभार्य आय जिसकी 60 प्रतिशत निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपये या 60 प्रतिशत से अधिक राशि की राशि या होने की संभावना नहीं है;

⁶¹ [(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, लेकिन सोलह वर्ष से अधिक नहीं, तब तक बीत चुके हैं जब तक कि भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय ब्याज सहित) के संबंध में आय, जो कर के लिए प्रभार्य है, निर्धारण से बच गई है।]

स्पष्टीकरण— कर से प्रभार्य आय का निर्धारण करने में जो इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण से बच गई है, धारा 147 के स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि वे उस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

(2) नोटिस जारी करने के संबंध में उप-धारा (1) के प्रावधान धारा 151 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे धारा 148 के तहत नोटिस दिया जाना है, वह धारा 163 के तहत एक अनिवासी के एजेंट के रूप में माना जाता है और नोटिस के अनुसरण में किया जाने वाला मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन उस पर ऐसे अनिवासी के एजेंट के रूप में किया जाना है, तो संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से ⁶²[छह] वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।”

58. वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित खंड (क) और (ख) 11-6-2001. उनके प्रतिस्थापन से पहले, खंड (ए) और (बी), जैसा कि प्रत्यक्ष कर कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा संशोधित किया गया है। 1-4-1989, नीचे पढ़ा गया है: “(क) ऐसे मामले में जहां धारा 143 की उप-धारा (3) या धारा 147 के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण किया गया है, -

(i) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि मामला उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन नहीं आता है;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, लेकिन सात वर्ष से अधिक नहीं, बीत गए हैं, जब तक कि कर के लिए प्रभार्य आय जो निर्धारण से बच गई है, उस वर्ष के लिए पचास हजार रुपये या उससे अधिक राशि की राशि या होने की संभावना नहीं है;

(ग) यदि सात वर्ष, लेकिन दस वर्ष से अधिक नहीं, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से बीत चुके हैं, जब तक कि कर के लिए प्रभार्य आय जो निर्धारण से बच गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपये या उससे अधिक राशि की राशि या होने की संभावना नहीं है;

(ख) किसी अन्य मामले में -

(i) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि मामला उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन नहीं आता है;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, लेकिन सात वर्ष से अधिक नहीं, बीत गए हैं, जब तक कि कर के लिए प्रभार्य आय जो निर्धारण से बच गई है, उस वर्ष के लिए पच्चीस हजार रुपये या उससे अधिक राशि की राशि या होने की संभावना नहीं है;

(iii) यदि सात वर्ष, लेकिन दस वर्ष से अधिक नहीं, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से बीत चुके हैं, जब तक कि कर के लिए प्रभार्य आय जो निर्धारण से बच गई है, उस वर्ष के लिए पचास हजार रुपये या उससे अधिक होने की संभावना है।”

59. वित्त अधिनियम, 2012, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-7-2012 द्वारा सम्मिलित।

60. "बच गए आकलन" और "एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि होने की संभावना" अभिव्यक्तियों के अर्थ के लिए, टैक्समैन की प्रत्यक्ष कर नियमावली, खंड देखें। 3.

61. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा अंतःस्थापित, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-7-2012

62. वित्त अधिनियम, 2012, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-7-2012 द्वारा "दो" के लिए प्रतिस्थापित।

31. वित्त अधिनियम, 2021 ने धारा 148 ए को "जांच करना, धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले अवसर प्रदान करना" शीर्षक के साथ जोड़ा। वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 01.04.2021 से प्रभावी धारा 148 ए निम्नानुसार है:

"148 ए. निर्धारण अधिकारी धारा 148 के अधीन कोई नोटिस जारी करने से पहले, -

(क) उस जानकारी के संबंध में, जो यह बताती है कि कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई है, किसी भी जांच का संचालन, यदि आवश्यक हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ;

(ख) निर्धारिती को, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, कारण बताने के लिए एक नोटिस देकर, उसकी सुनवाई करने का अवसर प्रदान करें, जो कम से कम सात दिन का हो और उस तारीख से तीस दिनों से अधिक का न हो, जिस दिन ऐसा नोटिस जारी किया गया है, या ऐसा समय जो उसके द्वारा इस संबंध में एक आवेदन के आधार पर बढ़ाया जा सके, कि धारा 148 के अधीन एक नोटिस उस जानकारी के आधार पर क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए, जो यह सुझाव देती है कि कर के लिए प्रभार्य आय उसके मामले में प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई है और जांच के परिणाम, यदि कोई हो, जारी किए गए हैं। खंड (क) के अनुसार;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिए गए निर्धारिती के जवाब पर, यदि कोई हो, विचार करें;

(घ) निर्धारिती के जवाब सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट जवाब उसे प्राप्त होता है, या जहां ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जाता है, उस महीने के अंत से एक महीने के भीतर, जिसमें समय दिया गया था या बढ़ाया गया था, एक आदेश पारित करके यह तय करें कि धारा 148 के तहत

नोटिस जारी करना उचित मामला है या नहीं। खंड (ख) के अनुसार उत्तर देने के लिए अनुमत समय समाप्त हो जाता है:

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहां -

(क) धारा 132 के अधीन तलाशी शुरू की जाती है या 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद निर्धारित के मामले में धारा 132ए के तहत लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या किसी भी संपत्ति की मांग की जाती है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से संतुष्ट है कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी में जब्त या धारा 132ए के तहत अधिग्रहित कोई भी धन, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज निर्धारित की है; या

(ग) निर्धारण अधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से संतुष्ट है कि धारा 132 के तहत तलाशी में जब्त की गई या धारा 132ए के तहत मांग की गई कोई भी लेखा पुस्तक या दस्तावेज, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, निर्धारित से संबंधित या उससे संबंधित या उसमें निहित कोई जानकारी, उससे संबंधित है।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अर्थ है धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी।]”

32. इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2021 के अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस के लिए समय सीमा को बदल दिया गया था। 01.04.2021 से प्रतिस्थापित धारा 149 निम्नानुसार है:

“ 28-36 [नोटिस के लिए समय सीमा।

149. (1) संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के तहत कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी, -

(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) के अंतर्गत न आए;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष, लेकिन दस वर्ष से अधिक नहीं, तब तक बीत चुके हैं जब तक कि निर्धारण अधिकारी के पास

लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य न हों जो यह प्रकट करते हों कि कर के लिए प्रभार्य आय, जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति के रूप में किया गया है, जो निर्धारण से बच गई है, उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपये या उससे अधिक की राशि है या होने की संभावना है:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पहले शुरू होने वाले प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए किसी मामले में धारा 148 के तहत कोई नोटिस किसी भी समय जारी नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा नोटिस इस धारा की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा से परे होने के कारण उस समय जारी नहीं किया जा सकता था, जैसा कि वे वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ से तुरंत पहले थे:

28-36. वित्त अधिनियम, 2021, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2021 द्वारा प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पहले, धारा 149, जैसा कि प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, डब्ल्यू. ई. एफ. प्रत्यक्ष कर कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-1989, वित्त अधिनियम, 2001, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-6-2001 और वित्त अधिनियम, 2012, डब्ल्यू. ई. एफ. 1-7-2012 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे नीचे पढ़ा गया है:

*149. नोटिस के लिए समय सीमा।-(1) संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, -

(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष बीत चुके हैं, जब तक कि मामला खंड (ख) या खंड (ग) के तहत नहीं आता है;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, लेकिन छह वर्ष से अधिक नहीं, तब तक बीत चुके हैं जब तक कि कर के लिए प्रभार्य आय जो निर्धारण से बच गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपये या उससे अधिक राशि की राशि या होने की संभावना नहीं है।

(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, लेकिन सोलह वर्ष से अधिक नहीं, तब तक बीत चुके हैं जब तक कि भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी भी संस्था में वित्तीय ब्याज सहित) के संबंध में आय, जो कर के लिए प्रभार्य है, निर्धारण से बच गई है।

स्पष्टीकरण।-कर से प्रभार्य आय का निर्धारण करने में जो इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण से बच गई है, धारा 147 के स्पष्टीकरण 2 के प्रावधान लागू होंगे क्योंकि वे उस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं। (2) नोटिस जारी करने के संबंध में उप-धारा (1) के प्रावधान धारा 151 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे धारा 148 के तहत नोटिस दिया जाना है, वह धारा 163 के तहत एक अनिवासी के एजेंट के रूप में माना जाता है और नोटिस के अनुसरण में किया जाने वाला मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन उस पर ऐसे अनिवासी के एजेंट के रूप में किया जाना है, तो संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से छह साल की अवधि समाप्त होने के बाद नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित उप-धारा (1) और (3) के प्रावधान, 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए भी लागू होंगे।”

*प्रासंगिक मामलों के कानूनों के लिए, टैक्समैन की मास्टर गाइड टू इनकम-टैक्स एक्ट देखें।

**"जारी" शब्द के अर्थ के लिए, टैक्समैन की प्रत्यक्ष कर नियमावली, खंड देखें। 3.

† "बच गए आकलन" और "एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि होने की संभावना" अभिव्यक्तियों के अर्थ के लिए, टैक्समैन की प्रत्यक्ष कर नियमावली, खंड 3. देखें।

बशर्ते कि इस उप-धारा के प्रावधान ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे, जहां धारा 153 ए या धारा 153 सी के तहत धारा 153 ए के साथ पठित नोटिस धारा 132 के तहत शुरू की गई तलाशी या लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या धारा 132 ए के तहत मांगी गई किसी संपत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले जारी किया जाना आवश्यक है:

परन्तु यह भी कि इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 148 क के खंड (ख) के अधीन जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार या उस अवधि के दौरान जिसके दौरान धारा 148 क के अधीन कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगाई जाती है, निर्धारित को अनुमत समय या विस्तारित समय को बाहर रखा जाएगा: परन्तु यह भी कि जहां तत्काल पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के तुरंत बाद, धारा 148 क के खंड (घ) के तहत आदेश पारित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध सीमा की अवधि सात दिनों से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को सात दिनों तक बढ़ाया जाएगा और इस उप-धारा के तहत सीमा की अवधि को तदनुसार बढ़ाया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "परिसंपत्ति" में अचल संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हो, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खाते में जमा राशि शामिल होगी।

(2) नोटिस जारी करने के संबंध में उप-धारा (1) के प्रावधान धारा 151 के प्रावधानों के अधीन होंगे।]"

33. वर्तमान मामले में, मूल्यांकन प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 148 ए खंड (बी) के तहत 23.03.2022 को नोटिस जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ता से कहा गया है कि वह अनुलग्नक 'ए' जो कि की धारा 148 के तहत एक नोटिस है,में निहित विवरणों को ध्यान में रखते हुए कारण बताए कि अधिनियम क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए। तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए गए दिनांक 23.03.2022 की सूचना के अनुलग्नक को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है:.

"श्री अंकित कुमार अग्रवाल, पैन-ए. आई. टी. पी. ए. 5485 ए. (जिसके बाद इसे "निर्धारिती" कहा जाता है) के मामले में जानकारी आई. एन. एस. आई. जी. एच. टी. पोर्टल से " विवरणी दाखिल न करने (एन. एम. एस.)" के मॉड्यूल के तहत प्राप्त हुई है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निर्धारिती ने विचाराधीन कारवाई के लिए आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया है।

अभिलेख पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निर्धारिती ने एफ. वाई. 2015-16 से संबंधित वित्त वर्ष 2014-15 में कुल रु. 2000000/- भारतीय स्टेट बैंक में जमा किये, इसके अलावा, निर्धारिती ने 2631400/- और र 4397919/- रुपये का लेनदेन भी किया है। निर्धारिती के पास एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 556584/- के इक्विटी शेयर की बिक्री है। ।

इस प्रकार, प्राप्त जानकारी के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि विवरणी दाखिल न करने वाले होने के बावजूद, विभिन्न स्रोतों से निर्धारिती की आय 9269898/-, रु है, उसी के लिए कर की पेशकश करने में विफल रहा है, कर के लिए प्रभार्य है, ए. वाई. 2015-16 के लिए मूल्यांकन से बच गया है।"

34. दिनांक 28.03.2022 की सूचना के अनुलग्नक से यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन अधिकारी के पास इनसाइट पोर्टल से विवरणी दाखिल न करने के

मॉड्यूल के तहत एक जानकारी थी जो उनके हाथ में एक स्पष्ट रूप से गलत जानकारी थी। उन्होंने कहा है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निर्धारिती ने विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया था। फिर से, यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। क्योंकि विभाग के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह एक गलती प्रतीत होती है और यह कट एंड पेस्ट के दौरान किया गया हो सकता है। इस न्यायालय को डर है कि इस तरह की दलीलों को प्रतिवादीओं से उचित स्पष्टीकरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के नाम का उल्लेख अनुलग्नक के पहले पैराग्राफ में किया गया है और फिर नोटिस जारी करने वाले प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के बारे में उल्लेख किया है जो सही डेटा नहीं है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने अपना आयकर विवरणी 30.03.2016 को दाखिल किया है और उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी अपलोड की गई थी।

35. इस न्यायालय ने आगे पाया कि अनुलग्नक के दूसरे पैराग्राफ में, यह कहा गया है कि निर्धारिती ने भारतीय स्टेट बैंक में कुल 20 लाख रुपये का लेन-देन किया था और 26,31,400 और 43,97,919 रुपये का लेन-देन भी किया था, लेकिन इन सभी लेन-देन पर बाद में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है और अंततः जो हुआ वह यह है कि निर्धारण अधिकारी ने 25,90,000-लाख रुपये के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की अनुमति नहीं दी है, जिसका दावा याचिकाकर्ता ने अपने आयकर विवरणी में किया था।

36. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ताका तर्क कि अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के अधीन जारी किए गए नोटिस के अनुलग्नक में, बचने वाले मूल्यांकन की राशि को 50 लाख रुपये से अधिक, केवल परिसीमा की अवधि से बचने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। इसमें बहुत बल है और याचिकाकर्ता के इस निवेदन को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है।

37. इस न्यायालय ने पाया कि धारा 149 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अधीन, पुरानी विधि के तहत परिसीमा की अवधि 4 साल थी, जब

तक कि वाद खंड (बी) या (सी) के अधीन नहीं आता था। यदि निर्धारण अधिकारी के पास लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य होते, जिससे पता चलता है कि कर के लिए प्रभार्य आय का प्रतिनिधित्व (i) एक संपत्ति (ii) लेनदेन के संबंध में या किसी घटना या अवसर के संबंध में व्यय के रूप में किया जाता है। या (iii) लेखा पुस्तकों में एक प्रविष्टि या प्रविष्टियाँ जो मूल्यांकन से बच गई हैं, संभवतः 50 लाख रु या उससे अधिक हो। प्रासंगिक समय पर, जब धारा 148ए (बी) के अधीन नोटिस जारी किया गया था, अधिकतम अवधि जिसके भीतर धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया जा सकता था, केवल 10 साल की थी, यदि छूट गई मूल्यांकन राशि रु 50 लाख या उससे अधिक की हो। तथापि, विभाग के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के अनुसार धारा 149 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पुरानी विधि के अधीन इस मामले में नोटिस चार साल के भीतर जारी किया जा सकता था, लेकिन प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से छह साल से अधिक नहीं बीत चुके हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले में छह साल की अवधि 31.03.2022 पर समाप्त हो गई होगी। यह नोटिस को 23.03.2022 को दिया गया था। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 29.03.2022 तक का समय दिया गया था। इस प्रकार, 23.03.2022 से 29.03.2022 तक की अवधि को परिसीमा की गिनती से बाहर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में, दिनांक 06.04.2022 नोटिस को 6 साल के भीतर जारी किया गया माना जाएगा।

38. यह आगे स्पष्ट है कि धारा 148ए (बी) के तहत नोटिस जारी करते समय, नोटिस जारी करने वाले प्राधिकरण ने न केवल गलत जानकारी पर भरोसा किया, बल्कि वह याचिकाकर्ता को इसके समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत करने में भी विफल रहा। इस संबंध में, राजीव बंसल (सु.को. के मामले में सालिक खान (सु.को.) के पैराग्राफ '5') और फैसले के पैराग्राफ '101' के मामले में इस न्यायालय की विद्वत समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है। हमने सालिक खान (सु.को.) के पैराग्राफ '5' और राजीव बंसल (ऊपर) के मामले में फैसले के पैराग्राफ '101' को तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत कियाः.

“5. जहाँ तक धारा 148 और धारा 148ए के तहत नोटिस का संबंध है, यह मुद्दा ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों में शामिल है। यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि धारा 149 धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक समय-सीमा का प्रावधान करती है जो उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत तीन साल है। केवल बचने वाले आकलन के लिए 10 साल की सीमा प्रदान की गई है जहां बचने वाला कर 50 लाख रु है। वर्तमान मामले में स्वीकार किया जाता है कि कुल आकलन केवल रु 31 लाख और अब बढ़ी हुई मांग रु 19 और उससे अधिक है। जहाँ तक धारा 148ए का संबंध है, इसे वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिनियम में 01.04.2021 से लाया गया था, जब धारा 148 भी प्रतिस्थापित की गई थी। धारा 148ए धारा 148 के तहत लेकिन उसी वित्त अधिनियम, 2021 के तहत नोटिस जारी करने से पहले प्रदान की गई पृष्ठछाछ और अवसर से संबंधित है। धारा 149 के अधीन प्रदान की गई सीमा अवधि को भी संशोधित किया गया था और इसे तीन साल तक कम कर दिया गया था जहां बख्शा गया आकलन रु 50 लाख से कम था।

101. धारा 148ए (बी) के तहत, निर्धारण अधिकारी को दो आवश्यकताओं का पालन करना होता है: (i) कारण दर्शाओ नोटिस जारी करना; और (ii) उन सभी प्रासंगिक सूचनाओं की आपूर्ति जो कारण दिखाओ नोटिस का आधार बनती हैं। प्रासंगिक सामग्री और जानकारी की आपूर्ति निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की अनुमति देती है। मानित नोटिस प्रभावी रूप से अधूरे थे क्योंकि निर्धारिती को प्रासंगिक सामग्री या जानकारी प्रदान करने की अन्य आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी। दूसरी आवश्यकता को राजस्व द्वारा केवल प्रासंगिक सामग्री या जानकारी की वास्तविक आपूर्ति द्वारा पूरा किया जा सकता था जो मानित सूचना का आधार बना।”

39. राजीव बंसल (सुपरा) के मामले में यह बात और सामने आई है, कि भारत संघ बनाम आशीष अग्रवाल एस. सी. सी. (2023) 1 617 में सूचित के मामले में माननीय न्यायालय ने निर्धारण अधिकारी को निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर निर्धारिती को राजस्व द्वारा भरोसा की गई प्रासंगिक जानकारी और सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया था। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 148ए (बी) के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस प्रभावी रूप से तभी जारी किया जाता है जब इसकी आपूर्ति. निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रासंगिक जानकारी और सामग्री के साथ की जाती है। विधिक कल्पना के कारण, निर्धारण अधिकारियों को धारा 148 ए (बी) नोटिस

के अनुसरण में कार्य करने से तब तक रोका गया जब तक कि संबंधित सामग्री निर्धारिती को प्रदान नहीं की जाती।

40. राजीव बंसल (सु.को.) और आशीष अग्रवाल के मामले में उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन गणेश दास खन्ना (सु.को.) के फैसले के पैराग्राफ '53' से मिलता है जिसमें आयकर कार्यवाही के लिए समय में कमी के संबंध में वित्त मंत्री का भाषण शामिल है। गणेश दास खन्ना (ऊपर) के मामले में पैराग्राफ '53', '53.1', '53.2' और '53.3' निर्णय इस प्रकार हैः.

"53. वित्त अधिनियम, 2021 के अधिनियमन के साथ शुरू किए गए प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा और योजना पर हमने जो ऊपर कहा है, उसके अलावा, हमारी राय में, नई व्यवस्था बनाने के लिए कारण को ध्यान में रखना होगा। इसके बारे में एक सुराग वित्त मंत्री के बजट भाषण में दिया गया है जो 1-2-2021 [(2021) 430 आई.टी.आर.(एसटी) 33] और वित्त विधेयक, 2021 [(2021) 430 आई.टी.आर.(एसटी)214] के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन के प्रासंगिक भागों में दिया गया है। सुविधा के लिए, संबंधित भागों को नीचे निकाला गया हैः

" वित्त मंत्री का भाषण

... आयकर कार्यवाही के लिए समय में कमी

153. अध्यक्ष, वर्तमान में, एक मूल्यांकन को 6 साल तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामलों में 10 साल तक फिर से खोला जा सकता है। नतीजतन, करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता में रहना पड़ता है।

154. इसलिए मैं मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए इस समय सीमा को वर्तमान 6 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं। गंभीर कर चोरी के मामलों में भी, केवल जहां एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छिपाने का सबूत है, मूल्यांकन को 10 साल तक फिर से खोला जा सकता है। यहां तक कि यह फिर से खोलना आयकर विभाग के सर्वोच्च स्तर के प्रधान मुख्य आयुक्त की मंजूरी के बाद ही किया जा सकता है।

मूल्यांकन से बचने वाली आय और खोज मूल्यांकन -

अधिनियम के तहत, आय से बचने वाले निर्धारण से संबंधित प्रावधानों में यह प्रावधान है कि यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कर के लिए प्रभार्य कोई भी आय किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से बच गई है, तो वह अधिनियम की धारा 147 के तहत अधिनियम की धारा 148 के तहत एक नोटिस जारी करके ऐसे वर्ष के लिए कुल आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन या पुनः गणना कर सकता है।

हालांकि, इस तरह से फिर से खोलना अधिनियम की धारा 149 में निर्धारित समय सीमा के अधीन है।

विधेयक में ऐसे मामलों के मूल्यांकन के लिए एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया का प्रस्ताव है। यह उम्मीद की जाती है कि नई प्रणाली के परिणामस्वरूप कम मुकदमेबाजी होगी और करदाताओं को व्यवसाय करने में आसानी होगी क्योंकि समय सीमा में कमी आई है जिसके द्वारा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनः संगणना के लिए एक नोटिस जारी किया जा सकता है। नई प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(iii) धारा 147 में निर्धारण अधिकारी को किसी भी निर्धारण वर्ष (जिसे प्रासंगिक निर्धारण वर्ष कहा जाता है) के लिए किसी भी आय से बचने वाले निर्धारण का आकलन या पुनर्मूल्यांकन या पुनः गणना करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

(vii) अधिनियम की नई धारा 148-ए का प्रस्ताव है कि नोटिस जारी करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी यदि आवश्यक हो तो पूछताछ करेगा और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। उसके उत्तर पर विचार करने के बाद, निर्धारण कार्यालय एक आदेश पारित करके यह तय करेगा कि क्या यह धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए एक उपयुक्त मामला है और निर्धारिती को इस तरह के नोटिस के साथ ऐसे आदेश की एक प्रति देगा। निर्धारण अधिकारी ऐसी कोई भी पूछताछ करने या निर्धारिती को अवसर प्रदान करने या ऐसा आदेश पारित करने से पहले निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा। हालांकि, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले पूछताछ की यह प्रक्रिया, अवसर प्रदान करने और आदेश पारित करने की प्रक्रिया, खोज या मांग के मामलों में लागू नहीं होगी।

(viii) अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा अधिनियम की धारा 149 में प्रस्तावित की गई है और यह नीचे दी गई है:

- सामान्य मामलों में, यदि संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन साल बीत चुके हैं तो कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष की अवधि से आगे की सूचना केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही ली जा सकती है।

- विशिष्ट मामलों में जहां निर्धारण अधिकारी के पास अपने पास साक्ष्य है जो यह दर्शाता है कि परिसंपत्ति के रूप में प्रतिनिधित्व की गई आय, पचास लाख रुपये या उससे अधिक होने की संभावना है, नोटिस तीन साल की अवधि के बाद जारी किया जा सकता है, लेकिन प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दस साल की अवधि से अधिक नहीं।

- एक अन्य प्रतिबंध यह प्रदान किया गया है कि अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस 1-4-2021 से पहले या उससे पहले शुरू होने वाले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी भी समय जारी नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा नोटिस उस समय जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक था। खंड (ख) के प्रावधान, जो प्रस्तावित संशोधन से ठीक पहले थे।

- चूंकि खोज या माँग मामलों में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या पुनः संगणना (जहाँ ऐसी खोज या माँग 31-3-2021 पर या उससे पहले शुरू की जाती है या की जाती है) अधिनियम की धारा 153-ए 153-बी, 153-सी और 153-डी के प्रावधानों के अनुसार की जानी है, उपरोक्त समय सीमा ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी।

- यह भी प्रस्तावित किया गया है कि धारा 148 नोटिस जारी करने के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्यों के लिए, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान करने में दिए गए समय या विस्तारित समय या उस अवधि के दौरान जिसके दौरान धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने से पहले ऐसी कार्यवाही पर किसी भी अदालत के आदेश या निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगाई जाती है, को बाहर रखा जाएगा। यदि ऐसी अवधि को हटाने के बाद, धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए किसी मामले की योग्यता के बारे

में आदेश पारित करने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए उपलब्ध समय सात दिनों से कम है, तो शेष समय को सात दिनों तक बढ़ा दिया जाएगा।”

(दबाव हमारा है)

53.1 जैसा कि ऊपर दिए गए उद्धरणों से स्पष्ट होगा, वित्त मंत्री के भाषण और ज्ञापन दोनों से, नई व्यवस्था के तहत फिर से खोलने की समय सीमा छह (6) साल से घटाकर तीन (3) साल कर दी गई थी और केवल "गंभीर कर चोरी के मामलों" के संबंध में, वह भी, जहां एक निश्चित अवधि में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छिपाने का सबूत पाया गया था, मूल्यांकन को फिर से खोलने की अवधि को दस (10) साल तक बढ़ा दिया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा की विस्तारित अवधि को लागू करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरती गई थी, प्रस्ताव यह था कि विभाग के उच्चतम पदानुक्रमित स्तर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी तरह, ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि नई व्यवस्था इस उम्मीद के साथ बनाई गई थी कि इसके परिणामस्वरूप कम मुकदमेबाजी होगी और करदाताओं को व्यवसाय करने में आसानी होगी, क्योंकि समय सीमा में कमी आई थी जिसके द्वारा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किया जा सकता था।

53.2. इस प्रकार, ज्ञापन के अनुसार, "सामान्य मामलों" में, यदि संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन (3) वर्ष बीत चुके हैं तो कोई नोटिस जारी करने का इरादा नहीं था। सूचना, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से निर्धारित तीन (3) वर्षों के बाद, केवल कुछ विशिष्ट मामलों में जारी की जा सकती है; ऐसा एक उदाहरण जो विधेयक में दिया गया है, वह है जहां निर्धारण अधिकारी के पास सबूत था कि बख्शी हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक थी।

53.3 संक्षेप में, जिस पृष्ठभूमि में मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई थी, उसे समग्र रूप से पढ़ने पर यह समझ में आता है कि जहां आय का पलायन 50 लाख रुपये से कम था, वहां सीमा की सामान्य अवधि यानी तीन (3) साल लागू होनी थी। इसकी तुलना में, दस (10) वर्षों की विस्तारित अवधि गंभीर कर चोरी के मामलों में लागू होगी जहां दी गई अवधि में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छिपाने का सबूत था।”

41. अभिलेखों से प्रकट होने वाले तथ्यों पर, इस न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को 1961 के अधिनियम की धारा 148 ए (बी) के तहत कोई प्रभावी कारण-बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.03.2022 के कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया, कारण बताओ नोटिस को अच्छा और विधि की आवश्यकता के अनुरूप नहीं बनाएगा। वित्त अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद प्रतिवादी 1961 के अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस जारी कर सकते थे, अगर धारा 149 (1) (बी) के तहत निर्धारित शर्त पूरी हो जाती।

42. ऊपर की चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही धारा 148 (ए) (बी) के तहत नोटिस में दी गई गलत जानकारी पर आधारित थी, जो किसी भी सामग्री/तत्वों द्वारा समर्थित नहीं थी, इसलिए, 06.04.2022 को धारा 148 का नोटिस जारी करके कार्यवाही की शुरुआत ही दूषित हो जाएगी।

43. नतीजतन, विवादित आदेश और याचिकाकर्ता के विरुद्ध उठाई गई मांग रद्द कर दी गई।

44. इस रिट आवेदन की अनुमति है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(अशोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।